

सम्पादकीय

उज्ज्वला योजना: कितनी हकीकत कितना फसाना

मार्च 2015 में हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों से घरेलू गैस उपभोक्ताओं से गैस सब्सिडी छोड़ने का आवाह किया था। सरकार द्वारा उस समय यही बताया गया था कि जनता द्वारा स्वेच्छा से सब्सिडी त्यागने के बाद जो धनराशि जुटाई जाएगी उससे उन गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा जो अभी तक लकड़ी या गोबर के उपरे आदि जलाकर चूल्हे पर खाना बनाने के लिये मजबूर हैं। इसी महत्वाकांक्षी योजना का नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसकी शुरुआत 2016 में जोरदार आयोजनों व जबरदस्त प्रवार प्रसार के साथ एक उत्सव के रूप में हुई थी। जिनतों पैसे गरीबों को गैस कनेक्शन व गैस चूल्हा आदि मुफ्त में उपलब्ध करवाने में सरकार ने खर्च किये होंगे संभवतः कम १ बेश उतने ही पैसे इन योजना का ठिंडोरा पीटने में खर्च कर दिये गये। अखाबार, टी बी, फ्लैट्स विवाहितानों के अलावा देश का शायद ही कोई ऐप्ट्रोल पंप ऐसा बचा हो जहाँ प्रधानमंत्री के बड़े चित्र साथ हम यह सुनते हैं कि इस योजना से महिलाओं को धुर्वे से निजात मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को खाना बनाने के लिए रोजाना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के बल्कि उहों जिन समस्याओं से जूझना पड़ता था उससे मुक्ति मिलेगी आदि, तो निश्चिव तौर पर ऐसा ही प्रतीत होता है गोया देश के गरीबों की इससे ज्यादा हितवितक सरकार दूसरी नहीं हो सकती। परन्तु इस योजना की धरातलीय स्थिति भी क्या वही है जो हमें सरकार व उसकी 'प्रकल्प' बनी बैठी सत्ता परस्त मीडिया द्वारा दिखाई जा रही है? जब प्रधानमंत्री इस योजना के लाभार्थियों से बात करते हैं तो चंद लोगों को बाकायदा प्रधानमंत्री से बातचीत का पूल रिहल्सल कराकर कैमरे के समक्ष बिठाया जाता है जो इस योजना की तारीफ करते हैं और सरकार का इन्यावाद करते हैं। परन्तु इस योजना की हकीकत तो कुछ और ही है। और इस हकीकत को जानने के लिये देश के किसी भी गांव या शहर के बी पी एल परिवर्ग के व्यक्ति से

—ङा वरिंद्र भाटिया—

मार्च 2015 में हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों से घरेलू गैस उपभोक्ताओं से गैस सब्सिडी छोड़ने का आवाह किया था। सरकार द्वारा उस समय यही बताया गया था कि जनता द्वारा स्वेच्छा से सब्सिडी त्यागने के बाद जो धनराशि जुटाई जाएगी उससे उन गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा जो अभी तक लकड़ी या गोबर के उपले आदि जलाकर बूल्टे पर खाना बनाने के लिये मजबूर हैं। इसी महत्वाकांक्षी योजना का नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसकी शुरुआत 2016 में जोरदार आयोजनों व जबरदस्त प्रवार प्रसार के साथ एक उत्सव के रूप में हुई थी। जिनमें पैसे गरीबों को गैस कनेक्शन व गैस चूल्हा आदि मुफ्त में उपलब्ध करवाने में सरकार ने खर्च किये होंगे संभवतः कम १ बेश उत्तरने ही पैसे इन योजना का ढिंडोरा पीटने में खर्च कर दिये गये। अखाबार, टी बी, फ्लैट्स विविधानों के अलावा देश का शायद ही कोई पेट्रोल पंप ऐसा बचा हो जहाँ प्रधानमंत्री के बड़े चित्र साथ हम यह सुनते हैं कि इस योजना से महिलाओं को धुर्वे से निजात मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को खाना बनाने के लिए रोजाना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के बलते उहें जिन समस्याओं से जूझना पड़ता था उससे मुक्ति मिलेगी आदि, तो निश्चित तौर पर ऐसा ही प्रतीत होता है गोया देश के गरीबों की इससे ज्यादा दिव्यितक सरकार दूसरी नहीं हो सकती। परन्तु इस योजना की धरातलीय स्थिति भी कथा बही है जो हमें सरकार व उसकी 'प्रक्रिया' बनी बैठी सत्ता परस्त मीडिया द्वारा दिखाई जा रही है? जब प्रधानमंत्री इस योजना के लाभार्थियों से बात करते हैं तो चंद लोगों को बाकायदा प्रधानमंत्री से बातचीत का पूल रिहल्सल कराकर कैमरे के समक्ष बिठाया जाता है जो इस योजना की तारीफ करते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। परन्तु इस योजना की हकीकत तो कुछ और ही है। और इस हकीकत को जानने के लिये देश के किसी भी गांव या शहर के बी पी एल परिवर्ग के व्यक्ति से

प्रणाली के सामने एक चुनौती शिक्षकों की कमी को दूर करना भी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार एकल शिक्षक के भरोसे बड़ी संख्या में स्कूल चल रहे हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक अन्य चुनौती उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह उल्लेखनीय है कि बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को शीर्ष 200 विश्व रैंकिंग में जगह मिलती है। यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं।

उल्लेखनीय है कि इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास पूर्व में भी किया जा चुका है, लेकिन उपलब्धियां सराहनीय नहीं रही हैं। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को यहां लागू करने की आवश्यकता है। इस नीति के तहत शिक्षा अधियान को सफल बनाने के लिए सरकार, नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, विशेषज्ञों, अधिभावकों, समुदाय के सदरप्तों को अपने स्तर पर काम करना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों, कार्यान्वयन एजेंसियों, छात्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के नेताओं के बीच एक सहजीवी संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए नवाचारों का एक परिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकता है जिसमें रोजगार के

बड़े अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि उद्योग शिक्षण संस्थानों से जुड़े हों। इसके अलावा कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों को विशेष महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और देश के डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टोरल प्रोग्रामों के अनुसंधान के लिए वित्त प्रदान करना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, प्रतिष्ठित उद्योग संगठनों, मीडिया हाउस और पेशेवर निकायों को भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को रेटिंग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक मजबूत रेटिंग प्रणाली विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी और उनके प्रदर्शन में सुधार करेगी। भारतीय विश्वविद्यालय अभी भी दुनिया के शीर्ष 200 रैंक वाले विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं हैं।

इस संबंध में विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों को संबंधित मानकों में आत्मनिरीक्षण और सुधार करना चाहिए। स्कूली शिक्षा में सुधार के अलावा शिक्षण और प्रशिक्षण विधायों में भी सुधार किया जाना चाहिए। यह भी देखना होगा कि सरकारें कानूनों को बदलने के बाद आवश्यक अतिरिक्त बजट प्रदान करें और उसे खर्च करने में सक्षम हैं या नहीं। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय

व्यवस्था महंगी होने की निम्नांभावना है। परिणामस्वरूप निम्नांग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा पास करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसी नीति के मुताबिक सरकार शिक्षा और जीडीपी का 6 फीसदी खर्च करेगी। हालांकि 1968 और 1986 तीव्रादीय शिक्षा नीति में भी यही लात कही गई थी, लेकिन वर्तमान समय में तस्वीर बेहद अलग है। अतः भारत सरकार जीडीपी का महज 2.7 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया। खुद भारत सरकार के अनुसार 2017-18 में हमने शोध कार्यों पर जीडीपी का महज 0.7 फीसदी खर्च किया। लेहाजा खर्च के मामले में सरकार तत्त्वावादी बड़ी उछाल कैसे लाएगी? उस पर स्थिति साफ नहीं हो सकी। उधर ग्रॉस एन्ऱोलेमेंट अनुपात हुंचाने का लक्ष्य 26.3 फीसदी से निम्नांभावना के द्वारा 50 फीसदी रखा गया है। निम्नांभावना के सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार तत्त्वावादी भारत में प्रति एक लाख छात्रावादी पर शोध करने वालों की अनुसंधान महज 15 है, जबकि चीन तत्त्वावादी ही संख्या में 111 बना रहा है।

भारत सरकार ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 15 करोड़ नई स्टीटॉं जोड़ने की लात कही है, लेकिन फिर वही स्वाल उठाता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के पास क्या खाका है? और सरकार इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी? उच्च शिक्षा में जीसी-एआईसीटीई की जगह एक

वस्तु बनती जा रही है, जिसे बाजार में निश्चित शुल्क से अधिक धन देकर खरीदा जा सकता है। परिणामतः शिक्षा में एक मिलन प्रकार की जाति प्रथा जन्म ले रही है जिसमें छात्र धन के आधार पर इंजीनियरिंग, मैनेजरेंट और डॉक्टर आदि उपाधियों के लिए प्रवेश पाकर उच्च भावना से ग्रस्त और धनाभाव के कारण प्रवेश से वंचित हीनभावना से ग्रस्त रहते हैं, जिससे असमानता की खाई बढ़ रही है। सामाजिक असंतुलन और विषमता इसका ही परिणाम है। सभी बिंदुओं को उत्तराधार में रखते हुए मानना है कि इस नई शिक्षा नीति के सकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलूओं की अपेक्षा अधिक है। मगर आगे की राह संघर्ष और चुनौतियों भरी है। सभी घोषणाओं को जर्मीन पर उत्तरने के लिए बुनियादी अवसरंचना की जरूरत होगी। इससे भी ज्यादा राजनीतिक इच्छाशक्ति को प्रबल करना होगा। नीति का क्रियान्वयन कितना मुश्किल है। इसके अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी शिक्षा के लिए आवंटित फड़ का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। शिक्षा में सुधार के लिए सबसे जल्दी यह है कि शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता को हर कीमत पर कायम किया जाए। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि केवल कांगड़ी खानापूर्ति के बजाय सही अर्थों में नीतियों को लागू करने की कोशिश की जाएगी।

सजग रहें, भगाएं त्यौहारों में कोविड को

—आर.के. सिन्हा—

कोविड और त्यौहारों के मौसम न बहुत ही घनिष्ठ और धातक अंबंध है। त्यौहारों में लोग धरों में मंदिरों, धार्मिक स्थानों, बाजारों व था सगे सम्बन्धियों के लिए नेकलने लगते हैं। नतीजा यह प्रोता है कि भीड़भाड़ बढ़ने के गरण कोविड का जिन सामने गतर खड़ा हो जाता है। पिछले दिन दशहरा और दिवाली के बाद कोविड के रोगियों की बढ़ी हुई अंख्या को सारे देश ने देखा था। वह जन्माष्टमी से त्यौहारों का जीजन चालू हो चुका है। सारे देश ने जन्माष्टमी का पर्व वैसे तो बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है, वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता, प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। कोरोना की काट वैक्सीन को लेकर अब ध्वनाने और गलतफही के जाल में फँसने का बक निकल चुका है। अब इसे फौरन लगाया ही लेना चाहिए। जो लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं उन्हें अपनी साचे बदल लेनी चाहिए। हमने पहले देखा था जब उड़ने सिख मिल्खा सिंह कह रहे थे के साथ जीवन सभी जीते हैं, लेकिन उसे खुली आंखों से देखते नहीं, जागते मन से जीते नहीं। इसीलिये जैन परम्परा में आध्यात्मिक पर्व पर्युषण को मनाया जाता है जो इस वर्ष 4 सितम्बर से 11 सितम्बर, 2021 तक आयोजित होगा। पर्युषण महापर्व के इन आठ दिनों में सभी जैन श्रद्धालुओं द्वारा तन और मन को साधनामय बना लेने के साथ मन को इतना माज लेने का प्रयत्न किया जायेगा कि अतीत की त्रुटियां को दूर करे हुए भविष्य में कोई भी गलत कदम न उठे, इसकी तैयारी होगी। इन आठ दिनों में एक ऐसा

मन और तन को उजालने का पर्व है पर्युषण

—लालत गग—

रातों बारे में जीवन के साथ जीवन सभी जीते हैं, लेकिन उसे खुली आँखों से देखते नहीं, जागते मन से जीते नहीं। इसीलिये जैन परम्परा में आध्यात्मिक पर्व पर्युषण को मनाया जाता है जो इस वर्ष 4 सितम्बर से 11 सितम्बर, 2021 तक आयोजित होगा। पर्युषण महापर्व के इन आठ दिनों में सभी जैन श्रद्धालुओं द्वारा तन और मन को साधनामय बना लेने के साथ मन को इतना मांज लेने का प्रयत्न किया जायेगा कि अतीत की त्रुटियां को दूर करते हुए भविष्य में कोई भी गलत कदम न उठे, इसकी तैयारी हो गी। इन आठ दिनों में एक ऐसा

पर्व है जैन एकता का प्रतीक पर्व है। जैन लोग इसे सर्वाधिक महत्व देते हैं। संपूर्ण जैन समाज इस पर्व के अपने तुल्य समझों। भगवान महावीर ने कहा—“मिती में सब भूएसु, वे रंग मज्जाण के पाणी”“सभी प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ वैर नहीं है।

मानवीय एकता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, मैत्री, शोषणविहीन सामाजिकता, अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों की स्थापना, अहिंसक जीवन आत्मा की उपासना शैली का समर्झन आदि तत्त्व पर्युषण महापर्व के मुख्य आधार हैं। ये तत्त्व जन-जन के जीवन का अंग बन सके, इस दृष्टि से इस महापर्व को जन-जन का पर्व बनाने के प्रयासों में जोड़ें।

